'गुलाबी नगरी' को पूरे देश में नंबर-1 स्मार्ट सिटी बनाने का विजन पेश किया भजनलाल सरकार ने

जयपुर में 9 स्थानों पर एलिवेटेड रोड और रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी होगा

- सांगानेर और विद्याधर नगर क्षेत्र में सड़क निर्माण और नवीनीकरण पर 165 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे
- जयपुर परकोटे और हैरिटेज बिल्डिंगों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया
- आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ पर रोप-वे बनाने की घोषणा, दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में ''राजस्थान मंडपम'' भी बनाया जायेगा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुलाबी नगरी (जयपुर) को देश में अव्वल स्मार्टसिटी बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसका रोडमैप बुधवार को विधानसभा में पेश हुए पहले बजट में खुलकर नजर आया। शहर में 9 जगहों पर फ्लाईओवर व रेलवे ओवर ब्रिज, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, जयपुर परकोटे के हैरिटेज संरक्षण, सड़कों के नवीनीकरण, पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं विकसित करने की घोषणाओं के साथ यह विजन पेश किया गया है।

भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया है। जयपुर में 9 स्थानों पर एलिवेटेड रोड व फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने, केन्द्र सरकार की मदद से जयपुर मेट्रो के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की सौगात दी गई है। जयपुर परकोटे और हैरिटेज बिल्डिंगों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्लान बनाकर काम शुरू करवाया जाएगा। सांगानेर एयरपोर्ट की टर्मिनल कैपेसिटी को 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 70 लाख करने और नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दीया कुमारी के विधानसभा क्षेत्रों में करीब 165 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का नेटवर्क बिछाया जाएगा। इसमें नई सड़क बनाने के साथ-साथ पुरानी सड़कों का नवीनीकरण होगा।

गुलाबी नगर के प्रमुख पर्यटन स्थल आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ किले पर रोप-वे भी बनाए जाएंगे। आमेर में लाइट एंड शो का बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। एस.एम.एस. स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए ''स्टेट ऑफ दि आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर'' स्थापित किया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में ''राजस्थान मंडपम'' भी बनाया जाएगा।

बजट घोषणाओं के मुताबिक जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइनें बिछाई जाएगी। ट्रैफिक की समस्या का समाधान के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस वॉलेंटियर्स दिए जाएंगे। प्रताप नगर स्थित आर.यू.एच.एस. अस्पताला में नया ट्रोमा सेंटर बनाया जायेगा। जयपुर के पर्यटन स्थलों पर इनफॉरमेशन टैक्नोलॉजी (आई.टी.) से संबंधित कार्य करवाए जाएंगे। जयपुर में पौधा रोपण और पार्क के विकास कार्य के लिए अलग से बजट दिया जाएगा। जयपुर में नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 20 करोड़ की लागत से वॉक इन एवियरी बनाई जाएगी। झालाना में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। जयपुर में अटल इनोवेशन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिसमें इनोवेशन से संबंधित लोगों को प्लेटफार्म दिया जाएगा।

इसके अलावा जनक मार्ग से शुरू होकर खातीपुरा मोड से क्वींस रोड होते हुए पुरानी चुंगी पर अंडरपास बनाते हुए झारखंड मोड से सिरसी रोड पर गौतम मार्ग तक एलीवेटेड रोड बनाया जायेगा। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) जल्द बनाई जाएगी।

सिरसी रोड पर राणा कुम्भा मार्ग से होते हुए सिरसी मोड तक एलिवेटेड रोड की डी.पी.आर. बनाई जाएगी। मुरलीपुरा इलाके में नाडी का फाटक पर 86.89 करोड़ की लागत से 4 लेन का आरओबी बनाने की घोषणा की गई है। सीतावाली फाटक से बैनाड़ फाटक के बीच 14.37 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी) बनाने की घोषणा की गई है। जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक पर 95 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जायेगा। सालीग्रामपुरा फाटक पर 86 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जायेगा।

अम्बेडकर सर्किल से ओ.टी.एस. चौराहा और यहां से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड बनायी जायेगी। इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डी.पी.आर. बनाने का काम जल्द शुरू होगा। सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक 170 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड बनेगा। जयपुर में कलेक्ट्री सर्किल से राजमहल चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने के लिए भी जल्द काम शुरू होगा।

कृषकों को बजट में कोई राहत नहीं दी है : पायलट

- राज्य सरकार का पहला पूर्ण बजट आमजन को निराश करने वाला

जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेताओं ने इसे दिशाहीन बजट बताया है और कहा है कि इसमें न तो जनता को राहत मिली है और न ही विकास का रोडमैप है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से भी इस बजट का कोई सरोकार नहीं है।

एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया पहला ही पूर्ण बजट आमजन को निराश करने वाला है। कृषि व कृषकों को इस बजट में कोई राहत नहीं दी गई है। सदन में एम.एस. स्वामीनाथन जी के कथन को पढ़ा परंतु एमएसपी को कानूनी दर्जा देने एवं उन्हें लागू करने को लेकर कुछ बोला होता तो बेहतर रहता। डबल इंजन की सरकार एमएसपी के कानूनी प्रावधान पर चुप है।

पायलट ने कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर भी बजट में कोई ज़िक्र नहीं किया गया। युवाओं के रोजगार, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर इस बजट में न तो कोई नीति दिखाई देती है और न ही कोई योजना। जमीनी वास्तविकता एवं समस्याओं से दूर यह बजट पूर्ण रूप से दिशाहीन एवं लोगों की अपेक्षाओं के विपरीत है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर बजट को लेकर लिखा कि, हमारी सरकार ने मिशन-2030 के तहत राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा था। मुझे आशा थी कि हमारी सरकार जाने के बाद भाजपा सरकार कम से कम राजस्थान की बेहतरी के लिए इस मिशन को ध्यान में रखकर काम करेगी और विकास की बेहतरीन योजनाएं लाएगी। बुधवार को राजस्थान सरकार की ओर से लाए गए बजट का शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं लगता है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट को लेकर कहा कि बजट में सिर्फ किलों और महलों की बातें गांव, गरीब, ग्रामीण, किसान की कोई बात नहीं है।राजस्थान की भाजपा सरकार का बजट पूर्णतया दिशाहीन है। बजट भाषण थोथी घोषणाओं, झूठे तथ्यों एवं हताशा से भरा हुआ था। बजट में किसान के लिए एमएसपी, कृषि लागत कम करने, आमजन को महंगाई से राहत देने एवं गरीब को 25 लाख तक नि:शुल्क इलाज देने का कोई प्रयास नहीं दिखा। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, नौकरीपेशा एवं मध्यमवर्ग के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की भी उपेक्षा की गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि बजट पूर्व अपेक्षित निराशाओ से ही पूर्णतह घिरा हुआ नजर आया। गाँव, देहात में किसान,जवान,मज़दूर किसी तबके के लिए इस बजट में कुछ दिखाई नहीं देता है ।इस पूरे बजट में सिर्फ़ भाजपा नेताओं की सामंतवादी विचारधारा नजर आती है।

सी.एन.जी. गैस पर वैट 14.50 से घटाकर 10 फीसदी किया

50 लाख रुपए की कीमत के फ्लैट्स तथा सोसायटी पट्टों पर खरीदे गए भूखंड़ों की रजिस्ट्री भी सस्ती करने का ऐलान किया

जयपुर (विसं)। भजनलाल सरकार ने अपने पहले बजट में सी.एन.जी. गैस और 50 लाख रु. की कीमत तक के फ्लैट्स पर रजिस्ट्री सस्ती करने की घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को सदन में बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। वित्त मंत्री ने राज्य में सीएनजी-पीएनजी पर लगने वाले वैट को 14.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने का ऐलान किया। वहीं फ्लैट की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 6 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।

देखा जाए तो वर्तमान में जयपुर शहर में सी.एन.जी. गैस की दरें 79.47 रुपए प्रति किलोग्राम है। एक किलोग्राम सीएनजी पर 14.50 फीसदी की दर से 11.52 रुपए वैट देना पड़ता है। इस तरह एक किलो सीएनजी गैस बाजार में 90.99 रुपए में मिलती है। अब राज्य सरकार द्वारा सी.एन.जी. गैस पर वैट की दर 14.5 फीसदी से कम करके 10 फीसदी कर दी है। अब एक किलो सीएनजी की कीमत 79.47 पर 10 फीसदी की दर से 7.94 रुपए वैट देना होगा। इस तरह एक किलोग्राम सीएनजी 87.41 रुपए की दर से उपलब्ध होगी।

इसी प्रकार वर्तमान में 50 लाख रुपए कीमत के फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने पर 6 फीसदी की दर से 3 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी के लगते हैं। स्टाम्प ड्यूटी पर 30 फीसदी सरचार्ज लगता है। फ्लैट की कीमत का एक फीसदी पंजीयन शुल्क चुकाना पड़ता है। अब स्टाम्प ड्यूटी 1 फीसदी घटाने के बाद आमजन को काफी राहत मिलेगी।

इसके साथ ही पत्नी, पुत्रवधू, पोता, पोती एवं दोहिता, दोहिती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर स्टाम्प डॅयूटी एवं पंजयीन शुल्क पर पूरी छूट दी गई हैं। इसी तरह परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन दो या अधिक गैर कृषि संपत्तियों के बदलने पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर दो प्रतिशत की गई हैं। सैनिकों एवं अद्धसैनिक बलो के शहीदों की वीरांगनाओं, उनके पुत्र, पुत्री या माता पिता को सरकार, निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निशुल्क आवास दिय जाने पर स्टाम्प डॅयूटी के साथ ही पंजीयन शुल्क की भी छूट दी गई हैं। निर्माणाधीन फ्लैट्स एवं भवनों पर जीएसटी राशि पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रावधान किया है।

सरकार ने अब उन मकानों-जमीनों की रजिस्ट्री पर भी छूट देने का ऐलान किया है, जिनकी खरीद-फरोख्त पूर्व में केवल सामान्य एग्रीमेंट के जरिए की गई हो। ऐसी संपत्तियों या सोसाइटी के पट्टों पर अब स्टाम्प ड्यूटी मौजूदा डीएलसी दरों की 20 फीसदी रेट पर लगाई जाएगी।

बजट पेश के दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का शायराना अंदाज

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए शायराना अंदाज में अपनी बातें रखी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे, संत हरिदास, निदा फाजली और एमएस स्वामीनाथन की पंक्तियां दोहराते हुए अपना विजन सदन के समक्ष रखा।

बजट भाषण के दौरान दीया कुमारी ने सबसे पहले निदा फाजली का शेर पढ़ा :

''सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो,
सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो;
किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं,
तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो।''

इसके बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सदन में कविता सुनाई।

''लेकर अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य नित करें
हम मानव कल्याण, दे सहारा करें असहाय वृद्ध जन
का सम्मान, दे नारी को प्रोत्साहन।
है भार युवा कंधों पर, आओ कंधे उनके मजबूत
बनाएं। आओ मिलकर विकास की ओर एक साथ
कदम बढ़ाए।
धरती ओढ़े चुनरी हरि साफ स्वच्छ रहे,
पर्यावरण रोशन कर घरों को उनके करें हर पल
तिमिर का हरण।
प्यास बुझे ढाणी-ढाणी, मगरे-मगरे पहुंचे
पानी, विकसित हो उद्योग, मिले सबको रोजगार हैं
मिलकर हमने ठानी।
मंद हो गई जो प्रगति, आओ फिर उसको
गतिमान बनाए।
आओ मिलकर विकास की ओर एक साथ
कदम बढ़ाए।
चलो मिलकर हम सब विकसित राजस्थान
बनाएं।

इसके बाद दीया कुमारी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रचना सदन में पढ़कर सुनाई।

टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की
छाती में उग आया नव अंकुर
झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात,
प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया
गाता हूं।
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को
चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी।
हार नही मानूंगा, रार नई ठानूंगा, काल के
कपाल पर लिखता-मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं।
गीत नया गाता हूं।

इससे पहले दीया कुमारी ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की पंक्तियां दोहराते हुए ''आर्थिक उन्नित और सामाजिक उत्थान की पूंजी औद्योगीकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ाने से हम रोजगार दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं और जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते है।''

जल संरक्षण, सिंचाई और नहरीतंत्र पर एक लाख करोड़ रु. खर्च करेगी सरकार : रावत

जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी विज़न को उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने बजट 2024-25 में पेश किया है। यह बजट महिलाओं,युवाओं, किसानों ,कर्मचारियों, उद्यिमयों, वंचितों,.जरूरतमंदो, सहित प्रदेश के सभी वर्गों की उम्मीदों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। विज़न राजस्थान-2047 को ध्यान में रखते आगामी पांच वर्षो में 10 संकल्पो में माध्यम से प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए यह बजट समर्पित है।

रावत ने कहा कि राजस्थान में जल संरक्षण, सिंचाई, नहरीतंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा संशोधित पी.के.सी लिंक परियोजना पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय होगी, जिसका लाभ किसानों एवं आमजन को मिलेगा। संशोधित पार्वती- कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे राज्य की करीब 40 प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल एवं 2.80 लाख से अधिक हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि एकीकृत ईआरसीपी परियोजना के प्रथम चरण में कार्यों के लिए 9600 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके है। साथ ही आगे के कार्यों के लिए 26 हजार 800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, ताकि जल्द से जल्द परियोजना का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके। रावत ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ जल संचय प्रणाली विकसित करने के लिए राजस्थान इरिगेशन वॉटर ग्रिड मिशन शुरु किया जाएगा। इसके तहत 50 हजार करोड रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बरसात एवं बाढ़ के दौरान व्यर्थ बहकर जाने वाले जल से बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ-साथ जल के सदुपयोग के लिए रन ऑफ वॉटर ग्रिड स्थापित किया जाएगा।

बजट में विकास का खाका : खर्रा

जयपुर। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राजस्थान के बजट की तारीफ करते हुए इसे प्रदेश के विकास का खाका बताया। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार का यह बजट ऐतिहासिक है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। 'गांव-गरीब से शहर-व्यापार की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से दूरी' घटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का विकास गारंटिड है। सिविल प्लानिंग से राजस्थान के विकास की रफ्तार में और तेजी आएगी। नगरीय निकायों में अंडरग्राउंड बिजली लाइन डाली जाएंगी, शहर के बाज़ारों में बायो पिंक टॉयलेट से स्वच्छता होगी।

प्रदेश को विकास के नए पथ पर ले जाने वाला बजट : शेखावत

जयपुर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सर्वसमावेशी विकास का बजट प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी को शुभकमानाएं दीं। अपनी प्रतिक्रिया में शेखावत ने कहा कि भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट हर वर्ग के सपने पूरे होने की गारंटी है। अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान को विकास के नए पथ पर लेकर जाएगी। इस बजट के माध्यम से राजस्थान देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। शेखावत ने कहा कि भजनलाल सरकार के बजट के दायरे से कोई छूटा नहीं है। हर वर्ग को यह बजट अपने लिए लगेगा और हर वर्ग स्वयं को सशक्त महसूस करेगा। नारी शक्ति, अन्नदाता, युवाओं और गरीबों का बजट में विशेष ख्याल रखा गया है। 5 साल में 4 लाख नौकरियों से युवा सशक्त होगा। ब्याज मुक्त लोन देने के अलावा किसानों के लिए कई घोषणाएं बताई हैं कि भाजपा सरकार किसानों की हितैषी है। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने से हमारी माताएं-बहनें का सशक्तीकरण होगा। साथ ही, महंगाई से राहत देने के लिए कई ठोस कदम बजट में उठाए गए हैं।

प्रदेश के 25 लाख घरों को नल से जोड़ेगी सरकार : कन्हैयालाल

जयपुर। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने वाला जनकल्याणकारी बजट है। यह परिवर्तित बजट 2024-25 गरीब, बेरोजगार युवा, महिलाएं और किसानों को समर्पित है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, कृषि एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही बजट में आमजन को राहत प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

जलदाय मंत्री ने कहा कि पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए ई.आर.सी.पी परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य आदेश जारी करने, पेपर लीक जैसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही, विद्युत तंत्र को मजबूत करने, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने, 60 हजार करोड रुपए के स्टेट हाईवे एवं अन्य सड़क निर्माण कार्य, पर्यटन को विकास देने के लिए नवीन पर्यटन नीति की घोषणा सभी वर्गों के विकास के संकल्प को साकार करने वाली है। सरकार द्वारा बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दिया गया है इससे न केवल प्रति वर्ष बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा बल्कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का निर्णय बेहद सराहनीय है।

राजस्थान के समग्र विकास को गति देगा बजट : अरुण चतुर्वेदी

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के प्रथम बजट को राजस्थान के समग्र विकास को गति देने वाला बताया है। राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत इस बजट में समाज के सभी वर्गों का हित दिखता है। गत कांग्रेस सरकार द्वारा विरासत में दी गई गम्भीर आर्थिक चुनौतियों के बाद भी भजनलाल सरकार ने प्रदेश के युवा, महिला, ग़रीब, किसान, श्रमिक, थडी-ठेले वालो औरउद्योगों के लिये प्रभावी घोषणाएं की है। साथ ही आधारभूत ढांचों के उन्नयन ई.आर.सी.पी. व यमुना जल योजनाओं की क्रियान्वित के लिये किये गये प्रावधानों ने भाजपा सरकार की प्रतिबद्धताओं को प्रकट करता है।

बजट में प्रत्येक वर्ग की सामाजिक सुरक्षा : अविनाश गहलोत

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा विधानसभा में पेश बजट समाज के प्रत्येक वर्ग को स्पर्श करता हुआ समावेशी बजट है।

बजट में सामाजिक सुरक्षा के लिए की गई घोषणाएं स्पष्ट करती हैं कि राज्य सरकार समाज के वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

विभिन्न आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों के रिपेयर व आवश्यक सामग्री के लिए 50 करोड़ रुपए, छात्रावासों के पुनर्निर्माण हेतु लगभग 45 करोड़ रुपए, छात्रावासों का मैस भत्ता 2500 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार रुपए करने, नशा मुक्ति केंद्र खोलने, एससी-एसटी एवं टीएसपी फंड की राशि बढ़ाकर 1500 करोड रुपए, दिव्यांग जनों के लिए 2000 स्कूटी वितरण, घुमन्तू जातियों के लिए मुख्यमंत्री घुमन्तू आवास योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और पेइंग गेस्ट सुविधा, अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम को 100 करोड रुपए की सहायता, ईडब्ल्यूएस के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण, जामडोली जयपुर का विस्तार व सुदृढ़ीकरण करने के लिए स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी घोषणाएं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी।

बजट में विकसित राजस्थान-2047 का विजन : डॉ.सौम्या

जयपुर। महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के बजट में विकसित राजस्थान-2047 का विजन है। आमजन की मूलभूत आवश्यकता बिजली, पानी, सड़क के विकास को दृष्टिगत रखते हुए विरासत भी विकास भी सोच के साथ धरोहर का संरक्षण सुनियोजित शहरी विकास का ध्यान रखा गया है। नगरीय निकायों में महिलाओं के लिये बॉयोपिंक टॉयलेट बनाने एवं कचरा संग्रहण एवं परिवहन से निस्तारण तक की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आईटी तकनीक का उपयोग करने, ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए समुचित व्यवस्था किये जाने, शहरों में ड्रेनेज, जल संरक्षण, जनसुविधा, सामुदायिक कार्य लखपति दीदी योजना और सबन्धी घोषणाएं सराहनीय है।

एनर्जी सेक्टर में व्यापक सुधार का रोडमैप : ऊर्जा मंत्री

जयपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विधानसभा में भजनलाल सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को सदन में जो घोषणाएं की हैं, उससे स्पष्ट है कि एनर्जी सेक्टर का कायाकल्प सरकार की प्राथमिकताओं में पहले पायदान पर है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आगामी 10 वर्षों की विद्युत मांग के दृष्टिगत ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना, वर्ष 2031-32 की ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए 2 लाख 25 हजार करोड़ के कार्य, प्रत्येक जिले में पीएम सूर्यघर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम तथा इनमें 2 मेगावाट क्षमता तक के डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत अनुदान, राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने, बिजली कनेक्शन से अब तक वंचित 2 लाख 8 हजार परिवारों को घरेलू कनेक्शन, प्रसारण क्षमता मजबूत करने तथा छीजत रोकने के लिए 765, 400, 220 तथा 132 केवी क्षमता के 68 नए जीएसएस, 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नए सोलर पार्क, ऊर्जा भंडारण के लिए नीति, बारां, भरतपुर एवं अन्य जिलों में पंप स्टोरेज से ऊर्जा उत्पादन जैसी घोषणाओं से ऊर्जा क्षेत्र के कायाकल्प की दूरदर्शी सोच को गति मिलेगी।

सार-समाचार

पर्यटन के अनुकूल है बजट : गजसिंह

जयपुर। इंडियन हैरिटेज होटल्स एसोसिएशन के महासचिव गजसिंह अलसीसर ने राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा घोषित बजट को वास्तव में प्रगतिशील और पर्यटन अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए नवीन पर्यटन नीति की घोषणा की जाएगी। बजट में राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के गठन की भी घोषणा की गई है। हैरिटेज, एडवेंचर, धार्मिक, ग्रामीण पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना सराहनीय कदम है। बुनियादी ढांचे समेत अन्य विकास कार्यों के लिए 5 हजार करोड़ रु. का फंड बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में किलों, महलों और स्मारकों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राजस्थान हैरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना भी की जाएगी।

सी.आई.आई. ने बजट को सराहा

अरूण मिश्रा और नितिन गुप्ता

जयपुर। सी.आई.आई. राजस्थान के अध्यक्ष अरुण मिश्रा और वरिष्ठ निदेशक नितिन गुप्ता ने राजस्थान के बजट को सराहा है। बजट में पर्यटन, कला एवं संस्कृति को लेकर की गई घोषणायें जैसे दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाना, काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर, पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास के लिए राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनाने की घोषणा स्वागत योग्य कदम हैं। यह कदम राज्य में पर्यटन और इससे जुड़े रोजगार को बढ़ावा देगा। नितिन गुप्ता ने कहा कि रीको को हस्तान्तरित औद्योकि क्षेत्र के भूरूपान्तरण, एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिये ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रीयल लैण्डस वेलिडेशन एक्ट एक बहुत ही जरूरी कदम साबित होगा। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित शुल्क को 50 रु. प्रतिवर्गमीटर से घटाकर 15 रु. प्रतिवर्गमीटर 5 वर्ष करना सभी के लिए राहत भरा कदम हैं।

'जयपुर को नंबर-1 बनाने वाला बजट'

मनोज सिंह गोतोड़

जयपुर। भाजपा नेता व सांगानेर क्षेत्र से पार्षद प्रत्याशी मनोज सिंह गोतोड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार द्वारा पेश राजस्थान के पहले पूर्ण बजट में राजधानी जयपुर को नंबर-1 शहर बनाने का विजन छिपा हुआ है। जयपुर में एलीवेटेड रोड्स के निर्माण के अलावा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, जयपुर परकोटे और हैरिटेज बिल्डिंगों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रु. का बजट देने, दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाने तथा जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ किले पर रोप-वे शुरू करवाने का फैसला सराहनीय है।

'बजट को अर्द्ध हितकारी बताया'

जयपुर। रविकाश फाइनेंसियल के डायरेक्टर विकास ओझा ने राजस्थान के बजट को अर्द्ध हितकारी बताते हुए कहा वित्त मंत्री ने बजट में दस संकल्पों के आगाज़ के साथ राहत का पिटारा अवश्य खोला है, मगर पैसे का प्रबंध कैसे होगा, इसकी जानकारी नहीं दी है। ओझा ने कहा बजट विकासोन्मुखी कहा जा सकता है, लेकिन महंगाई पर काबू कर जनता को राहत देने पर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने को सरकार का आशावाद बताया।

संतुलित बजट : सीए सुधीर भंसाली

जयपुर। राजस्थान सीए सोसायटी के अध्यक्ष सी.ए. सुधीर भंसाली ने राजस्थान के बजट को संतुलित बताया। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण पूंजी व्यय योग में 15,500 करोड़ रुपये की वृद्धि है जो कि इस बात का द्योतक है कि राजस्थान आने वाले समय में विकास की ओर अग्रसर है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि से बाजार में मुद्रा का चलन ज्यादा होगा, जिससे अन्य व्यवसायों की वृद्धि भी निश्चित होगी। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा भी महत्वपूर्ण है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि एवम नई भर्तियों की घोषणा भी की सीए भंसाली के अनुसार वित्त मंत्री ने राज्य की जनता का स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया है। पुराने विवादों के सुलझाने के लिए विभिन्न एमनेस्टी स्कीम लागू किया जाना। वैट एमनेस्टी स्कीम सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें 10 लाख रुपये तक की मांग राशि जो कि रिपिल्ड एक्ट्स के प्रकरणों से संबंधित है को माफ़ किया जाएगा तथा उससे अधिक की मांग राशि को 10-20 परसेंट कर जमा करने पर शेष मांग अपलेखित की जाएगी।